हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 21 मई 2026, समय 13:05 (5 मिनट)

हरियाणा के स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विद्यालय आधारभूत संरचना की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा भी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा के सुझावों को स्वीकार करते हुए हरियाणा के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रमदान को अनिवार्य किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।

शिक्षा मंत्री के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। शिक्षकों के मोबाइल विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में जमा रहेंगे तथा शिक्षण कार्य के दौरान मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालयों की शुरुआत की।

वर्ष 2026-27 के बजट घोषणा के अनुरूप पहले चरण में चिन्हित 250 विद्यालयों का शुभारंभ किया गया।

इन विद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा ।

ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे तथा इनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में आधुनिक संसाधन, बेहतर आधारभूत ढांचा, प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

****

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। यह बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट-यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थी और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में, श्री प्रधान ने नीट-यूजी की पुन: परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।

****

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राज्य के सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे अपनी- अपनी पार्टियों के लिए बूथ लेवल एजेंट 1 व 2 की नियुक्ति आगामी सप्ताह के अंदर करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सूचित करें। क्योंकि शुद्ध व सटीक मतदाता सूची तैयार करवाने में बीएलओ व बीएलए एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में विशेष गहन पुननिरीक्षण 2026 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 15 जून से आरंभ किया जा रहा है, इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर- घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि राज्य में मतदाता सूचियों की मैपिंग का कार्य 64 प्रतिशत हो चुका है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में मतदाताओं के सहयोग के लिए विधानसभा वार व सभी जिला मुख्यालय पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उपायुक्त -कम -जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष संघन संशोधन कार्यों के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान करना राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 'CM विंडो' पर मिली शिकायतों का तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कल चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर 'CM विंडो' पर मिली शिकायतों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सभी जिलों के उपायुक्त , पुलिस अधीक्षक और मंडलायुक्त इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

विभिन्न विभागों से संबंधित जिलेवार शिकायतों की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में तेज़ी लाएं और यह सुनिश्चित करें कि सभी शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही हो जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 'CM विंडो' से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी और समन्वय के लिए सभी विभागों के साथ-साथ जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

सभी उपायुक्तों से विस्तृत जानकारी लेते हुए, मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि 'CM विंडो' की शिकायतों के साथ-साथ, 'Harpath' ऐप के तहत लंबित मामलों की भी नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि शिकायतों का पूरी तरह से और व्यापक समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

****